Embargoed till 19:30 hrs IST
on 25 Jan 2007

25 जनवरी, 2007

58वें गणतंत्र दिवस-2007 की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति
डॉ. आ.प.जै. अब्दुल कलाम का राष्ट्र के नाम संदेश

मैं अपने राष्ट्र को क्या दे सकता हूं?

'संकल्पना राष्ट्र को प्रेरित करती है'

प्यारे देशवासियो,

भारत के 58वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को मेरी शुभकामनाएं। मैं जल, थल और आकाश में हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाली सशस्त्र सेनाओं और अर्ध सैन्य बलों के सदस्यों और अन्य आंतरिक सुरक्षा बलों सहित केन्द्र और राज्य स्तर के पुलिस बलों को भी हार्दिक बधाई देता हूं।

दोस्तो, मैं सोच रहा था कि 58वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मैं आपके साथ किस विषय पर चर्चा करूं। देश के विभिन्न हिस्सों की अपनी यात्रा के दौरान लोगों और खासकर युवाओं से मुझे जो संदेश मिला क्या मैं उसके बारे में बात करूं या बिनौला के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम करने वाले पंजाब के किसानों की सफलता पर गौरवान्वित होने के बारे में आपसे बातचीत करूं या आपको बताऊं कि उत्तर-पूर्व राज्य का एक गांव कैसे देसी रेशम कुटीर उद्योग में क्षमता हासिल करके समृद्ध बन गया या मैं गुजरात राज्य के सभी गांवों तक बिजली पहुंचने पर प्रसन्न गांववासियों के बारे में आपसे बातचीत करूं या मैं देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले अनेक महान लोगों के बारे में आपसे बातचीत करूं या फिर पंजाब में एक प्रदूषित नदी को स्वप्रयासों से स्वच्छ बनाने के लिए तीर्थयात्रियों का नेतृत्व करने वाली एक शख्सियत के बारे में आपसे बातचीत करूं या आपको बताऊं कि कैसे एक दैवीय मनुष्य ने कोच्चि के सुनामी प्रभावित क्षेत्र में अरब सागर की झील के ऊपर प्रायद्वीपीय क्षेत्र को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पुल का निर्माण किया या फिर मैं आपको तमिलनाडु के एक लाख की जनसंख्या वाले ऐसे 65 गांवों के बारे में बताऊं जिन्होंने पुरा के जरिए आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण किया या मैं आपको एक राज्य की ऐसी न्यायिक प्रणाली के बारे में बताऊं जो वास्तविक भूकंप पीड़ितों को सही समय पर एक ही स्थान पर मुआवजा देने के लिए साझीदार बन गयी।

मैं क्या दे सकता हूं?

अस्सी के दशक में बच्चे मुझसे प्रश्न किया करते थे, "मैं भारत का गीत कब गाऊंगा?" आज युवा मुझसे पूछ रहे हैं, "मैं भारत के लिए क्या कर सकता हूं?" इससे पता चलता है कि राष्ट्र प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रश्नों में यह बदलाव वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन का सूचक है। इसके अलावा, मुझे बहुत से ई-मेल और पत्र मिलते हैं, जिनमें यह पूछा जाता है कि "मैं भारत को क्या दे सकता हूं?" पत्र, संदेश और ई-मेल पढ़कर और लोगों से की गयी बातचीत से, मुझे ऐसे बहुत से अवसर दिखाई देते हैं जिनसे प्रत्येक नागरिक अपना योगदान दे सकता है। मेरे मन में इसी विषय पर आपसे बातचीत करने का विचार आया : मेरे इस संबोधन का विषय होगा, "मैं अपने राष्ट्र को क्या दे सकता हूं?"

2007 के राष्ट्र का परिदृश्य

भारतीय इतिहास में हमारे राष्ट्र के समक्ष शायद ही ऐसा समय आया हो जब हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हो, विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा हो, घरेलू निवेश के साथ-साथ निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा हो, भारतीय प्रबंधन और उद्यम प्रतिभाओं को विश्व में सफलता मिल रही हो, प्रौद्योगिक कौशल को विश्व मान्यता मिल रही हो, 54 करोड़ युवाओं की ऊर्जा हमारे पास हो, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे ढाई करोड़ से ज्यादा भारतीय मूल के लोग एक सूत्र में बंधे हों और बहुत से विकसित देशों द्वारा भारत में अनुसंधान और विकास केंद्रों की स्थापना के साथ-साथ हमारे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों में निवेश करने में इतनी दिलचस्पी दिखाई हो। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का अन्तर और एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की झूठी मानसिकता मिट रही है। इसके अलावा, अब ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो रही है कि बहुत से युवक नौकरी करने की बजाय अपने नए उद्यम स्थापित कर रहे हैं।

विविध संस्कृति, भाषा और पंथ वाले एक अरब लोगों को नेतृत्व प्रदान करना, वास्तव में हमारे राष्ट्र की एक प्रमुख क्षमता है। उसके अलावा, विश्व बिरादरी हमारी प्रौद्योगिक क्षमता और हमारी सभ्यता से मिले नैतिक मूल्यों का बहुत सम्मान करती है। विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारत में निवेश करना आकर्षक लग रहा है क्योंकि यहां मिलने वाला लाभ अधिक और निश्चित है। भारतीय उद्यमी भी विदेशों में निवेश कर रहे हैं और नए व्यापारिक उद्यमों की स्थापना कर रहे हैं। हमारा सकल घरेलू उत्पाद सात सौ उनतीस बिलियन अमेरिकी डॉलर है और यह 10 प्रतिशत वार्षिक दर से लगातार बढ़ रहा है। इस बढ़ोतरी से अन्य क्षेत्रों के अलावा किसानों, कामगारों, पेशेवर लोगों के कल्याण में वृद्धि होगी और उद्यमी, व्यापारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर और समाज के अन्य सभी वर्ग रचनात्मक बनेंगे। आज, खुली आकाश

नीति और प्रतिस्पर्द्धा के कारण बढ़ते हुए मध्य वर्ग के लिए हवाई यात्रा करना आसान हो गया है। रेलवे ने भी कई सुधार किए हैं और लोग अब इंटरनेट के जरिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। यात्रा में क्रांति आने से न केवल लोग एक-दूसरे के संपर्क में आए हैं बल्कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था में भी तेजी आई है। देश में दूर-घनत्व बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है। मोबाइल फ़ोन आम आदमी तक पहुंच रहे हैं और उसकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। वन इण्डिया योजना के तहत देश भर में आसान और किफ़ायती दरों पर फोन करने की सुविधा उपलब्ध हो सकी है। हमारी सूचना संचार प्रौद्योगिकी लगभग 24 बिलियन डॉलर मूल्य का निर्यात कर रहा है और भारतीय औषधि उद्योग को संसार में चौथा स्थान हासिल है और यह लगभग 4 बिलियन डॉलर मूल्य के उत्पाद निर्यात कर रहा है। हमारा 44 बिलियन डॉलर का आटोमोबाइल उद्योग 17 प्रतिशत वार्षिक दर की रफ़्तार से बढ़ रहा है। पिछले 8 महीने में हमारा कुल निर्यात 80 बिलियन डॉलर को पार कर गया है।

हमारी वायु अंतरिक्ष और वैमानिक उपलब्धियां शानदार हैं। विभिन्न रिज़ोल्यूशन और स्पक्ट्रेमी बैंड वाले छह सुदूर संवेदी उपग्रह प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए अपनी मूल्यवान सेवाएं दे रहे हैं। 10 जनवरी 2007 को अंतरिक्ष कैप्स्यूल प्राप्ति प्रयोग (एस आर ई) सहित पी एस एल वी-सी 7 द्वारा छोड़े गए कार्टोसैट-2 और दो अन्य विदेशी उपग्रहों से इस क्षमता में और वृद्धि होगी। सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग करने के बाद अंतरिक्ष कैप्स्यूल प्राप्ति प्रयोग (एस आर ई) भारतीय समुद्र में सफलतापूर्वक लौट आया है, यह एक और प्रौद्योगिक सफलता है। आज हमारे पास शिक्षा के लिए एक विशेष एड्यूसैट सहित अंतरिक्ष कक्षा में नौ भू-स्थैतिक उपग्रह हैं। देश ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और दूर संचार के क्षेत्र में हुई प्रगति का दूर-शिक्षा के साथ-साथ दूर चिकित्सा नेटवर्क और ग्राम संसाधन केंद्र निर्मित करने में सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। देश के किसी भी भाग में रहने वाले 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की उत्तम शिक्षा की जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार ने 'साक्षात' नाम से एक शिक्षा पोर्टल की शुरुआत की है। ब्रॉडबैंड सभी जिलों के खंड स्तर तक पहुंच चुका है। शैक्षिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के लिए विदेशी विद्यार्थी भारत आ रहे हैं। बहुत से विदेशी संस्थानों ने भारतीय विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से कार्य करना शुरू कर दिया है। भारत के अनुभव से 53 देशों को जोड़ने वाला पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क स्थापित हो गया है। देश ने दो सामरिक मिसाइल प्रणालियां शुरू कर दी हैं। एक अंतरराष्ट्रीय साझीदार के साथ मिलकर अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली का वाणिज्यिक उत्पादन भी होने लगा है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कम होकर 22 प्रतिशत रह गयी है और साक्षरता दर जल्द ही 75 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। रोजगार योग्य 40 करोड़ लोगों की जनसंख्या में से लगभग 9 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। केंद्र सरकार ने समाज के सभी वर्गों तक

विकास का बराबर लाभ पहुंचाने के लिए विशाल परिव्यय वाला भारत निर्माण कार्यक्रम नामक एक व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम आरंभ किए हैं। देश की अनेक राज्य सरकारों और निजी संस्थाओं द्वारा पुरा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से आज कई पुरा समूह काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार पहले चरण में, देश के प्रत्येक जिले में दो पुरा समूह शुरू करने की योजना बना रही है। सभी तबकों के लोग मार्गदर्शक ताकत बन सकते हैं और वे राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में साझीदार बन सकते हैं और अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। राज्य सरकारों ने 2020 की संकल्पना के लक्ष्यों को साकार करने के लिए ग्रामीण और बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के साथ-साथ अनेक नए मिशन आरंभ किए हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में, मैं 2020 के परिदृश्य के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा, हमें एक राष्ट्र के रूप में, इसके लिए कार्य करना होगा।

2020 का परिदृश्य

मैं समझता हूं कि यदि हम पारदर्शिता के साथ मिशन पद्धति से विकास की राजनीति को केन्द्र में रखकर, समग्र रूप से कार्य करें तो वर्ष 2020 से पहले ही भारत विकसित देश बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे न रहे और देश में शत-प्रतिशत साक्षरता हो। भारत की मानव विकास सूची वर्तमान 127 से घटकर 50 हो जाएगी। प्रत्येक भारतीय अच्छे विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में रोजगार पाने के योग्य कौशल से युक्त उच्च स्तरीय प्रशिक्षण से परिपूर्ण होगा। सरकार से सरकार और सरकार से नागरिकों के बीच सभी आदान-प्रदान ई-शासन के जरिए होंगे और नागरिक पहचान-पत्र होने से शासन प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। दूर-घनत्व लगभग 75 प्रतिशत तक हो जाएगा। हमारे सभी गांवों में निर्बाध और लगातार बिजली की आपूर्ति होगी। नदियों और जलाशयों को आपस में जोड़ने और जल संग्रहण, जल के पुनर्चक्रण और जल प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सिंचाई, पेय जल, उद्योग, नौवहन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जल का समान वितरण हो सकेगा। देश के किसी भी हिस्से में पानी की कमी नहीं रहेगी और न ही बाढ़ और जल भराव आदि के कारण कोई आपदा आएगी। भारत ऊर्जा सुरक्षा हासिल कर लेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य करेगा। भारत के प्रत्येक घर में और सभी भारतीयों और विदेशी पर्यटकों को साफ-सफाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, लघु और सूक्ष्म जलीय ऊर्जा और थोरियम आधारित न्यूक्लियर ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा का अधिक प्रयोग करेंगे जिससे प्रदूषण में कमी आएगी। सक्रिय और नयी उद्यम पूंजी प्रणाली और स्कूल व कॉलेजों में उद्यमशील प्रशिक्षण के जरिए हमारे पास

अधिक उद्यम होंगे। इसके परिणामस्वरूप रोजगार पाने वालों की अपेक्षा रोजगार देने वालों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। नयी-नयी योजनाओं द्वारा सक्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली से सुदूर क्षेत्रों में रहने वालों सहित देश के सभी लोगों को किफ़ायती मूल्य पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। उच्च शिक्षा में सभी को अपनी-अपनी रुचि के विषय चुनकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आप सबको देश में अभाव और नियंत्रण के स्थान पर समृद्धि के दर्शन होंगे। आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास उपलब्धियों के अलावा, भारत सामरिक महत्त्व के क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थित दर्ज करवाएगा और विश्व शांति में भी योगदान देगा। हमारी समृद्धि को बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी और आर्थिक प्रगति प्राचीन काल से संजोयी हमारी सभ्यता को कायम रखेगी। यह अद्भुत मेल हमारे विकास को ठोस और मजबूत बनाएगा और इससे शांतिपूर्ण, सुरक्षित, खुशहाल तथा समृद्ध समाज का निर्माण होगा।

यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विकास के एक राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता है। हमारे प्रजातंत्र के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक घटक को इस आंदोलन में हिस्सा लेना होगा। इस विकास आंदोलन में लोगों की सहभागिता की क्या रूपरेखा होगी? विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए लोगों की भागीदारी अनेक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में होनी चाहिए, जैसे सभी तक पहुंच, लोगों को मिलने वाली सेवा के बारे में लोगों के सुझाव, मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता, गृहणियों की भूमिका, पर्यावरण विकास, राजनीति में युवाओं की भागीदारी।

सभी तक पहुंच

सरकार ने वर्ष 2004-2005 को आधार मानते हुए 2005-2006 में कृषि क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता को दुगुना कर दिया है। नाबार्ड और बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा और जरूरतमंद किसानों को बिना कठिनाई के लघु ऋण निवेश मुहैया करवाने के तरीके ढूंढ़ने होंगे ताकि वे शोषक तत्त्वों के चंगुल में ना फंसे। इसी प्रकार, कृषि शोधकर्ताओं, शैक्षिक संस्थाओं के कर्मियों, गैर सरकारी संगठनों और उद्योग जगत को किसानों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उत्पादकता, संग्रहण, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन बढ़ाने के लिए उन्हें सक्षम बनाना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें पूरे ग्रामीण क्षेत्र के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए गांव की प्रमुख क्षमता पर आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु 'प्रति ग्राम समूह एक उत्पाद' की तर्ज पर गैर कृषि कार्यों में किसानों की मदद करनी चाहिए। बीमा कंपनियों को किसानों को जोखिम सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कम लागत के चिकित्सीय बीमा के अलावा, लघु बीमा, फसल बीमा और पशु बीमा के लिए भी आगे आना चाहिए। इसी प्रकार सुदूर क्षेत्रों में रहने वालों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए उत्तराखण्ड की तरह मोबाइल उपचार क्लीनिक जैसी इकाइयां सभी जिलों में शुरू की जा सकती हैं। हाल ही में,

शीघ्र न्याय देने के लिए विभिन्न स्तरों पर हमारी न्यायिक प्रणाली द्वारा कानूनी सहायता केंद्र, मध्यस्थता और समझौते, चल अदालत और लोक अदालत और कार्य दिवस और प्रतिदिन काम के घंटे बढ़ाने के अनेक प्रयास देखने को मिले हैं। ग्रामीण नागरिकों के घर पर न्याय पहुंचाने के लिए चल अदालतों द्वारा इन प्रयासों को और मजबूत किया जा सकता है। कॉर्पोरेट क्षेत्र भी 'कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी' के एक आवश्यक हिस्से के रूप में सभी तक पहुंचने के बारे में सोच सकता है। इस संचार प्रधान विश्व में, संचार सुविधा-प्राप्त वर्ग के बाद अब सुविधाओं को आगे बढ़ाकर इससे वंचित लोगों तक पहुंचाना हमारी प्रौद्योगिकी क्रांति का हिस्सा होना चाहिए।

सेवाओं की प्रतिपुष्टि (फ़ीडबैक)

भारत को बहुत सी सेवाओं और ज्ञान उत्पादों के बाहरी स्रोत के लिए (आऊटसोर्सिंग) एक सर्वोत्तम स्थान के रूप में जाना जाता है परंतु हमें अभी भी अपने समाज में इन सेवाओं को मान्यता देने और इन सेवाओं के भुगतान के लिए खुद को परिपक्व बनाना है। हालांकि विकसित देशों में सरकार और कार्पोरेट से नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता द्वारा उनका विकास मापा जाता है। सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने की एक प्रणाली प्रतिपुष्टि है। सभी को बिना भय और पक्षपात के अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। इस राय से सेवा प्रदाता, चाहे कोई भी सेवा हो, उसमें निरंतर सुधार कर सकता है। हमें बिजली, पानी, टेलीफोन, गैस, परिवहन, शिक्षा, बीमा, बैंकिंग, कानून और पुलिस जैसी सेवाओं को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। सेवा प्रदाता चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र का, उसे सही भावना से लोगों की राय माननी चाहिए और ग्राहक को अल्पकालिक और दीर्घकालिक संतुष्टि देनी चाहिए। ग्राहकों को भी सकारात्मक प्रगति को स्वीकार करना चाहिए और सुधारों का स्वागत करना चाहिए। इस परिदृश्य से सेवा के प्रति गौरव और प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी।

लोगों से सीधे मिलने के अलावा वेबसाइट और पोर्टल लोगों की राय प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। मैं बहुत सी एजेंसियों की सरकारी वेबसाइटें देखता रहा हूं। अगर वेबसाइट नवीनतम जानकारी उपलब्ध नहीं करवाती है तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है और जिस उद्देश्य के लिए उसे तैयार किया गया है, वह समाप्त हो जाता है। यह बहुत ज़रूरी है कि इन वेबसाइटों को अद्यतन रखा जाए, ताकि ये नवीनतम जानकारी और सुझाव देने में सक्षम बनी रहे। वेबसाइट में किसी खास सुझाव पर की गयी कार्रवाई की भी सूचना दी जा सकती है। यह जरूरी है कि सेवा प्रदान करने वाला संगठन एक प्रयोक्ता समूह बनाए और सेवा में सुधार करने के लिए नियमित रूप से उनसे मिले। सरकारी अधिकारियों को लोगों के निरंतर संपर्क में रहने के लिए ई-शासन पोर्टल और ई-मेल का प्रयोग करना चाहिए और आवश्यक

कार्रवाई करनी चाहिए। हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किया गया सूचना अधिकार अधिनियम प्रशासन में पारदर्शिता की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम है।

वैश्विक मानव संसाधन कैडर

इस समय हमारे विश्वविद्यालयों से हर वर्ष 30 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे हैं और दसवीं और बारहवीं कक्षा पूरी करके रोजगार ढूंढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक वर्ष में तकरीबन 70 लाख है। इस प्रकार हर वर्ष लगभग एक करोड़ युवा रोजगार पाने की प्रतीक्षा में रहते हैं। 21वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञान प्रदान करने, ज्ञान रचना और ज्ञान बांटने के कार्य के लिए भारत को बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त प्रतिभावान युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय, भारत में 25 वर्ष से कम आयु के 54 करोड़ युवा नागरिक हैं। वर्ष 2050 तक यह संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। इस संसाधन को ध्यान में रखते हुए, विश्वविद्यालयों और शिक्षा प्रणालियों को विद्यार्थियों के दो संवर्ग तैयार करने चाहिए : (1) विशेष कौशल की विशिष्ट जानकारी से युक्त युवाओं का वैश्विक संवर्ग (2) उच्च शिक्षित युवाओं का एक अन्य वैश्विक संवर्ग। इन संवर्गों की आवश्यकता न केवल भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बल्कि विभिन्न देशों की मानव संसाधन जरूरतों को पूरा करने के लिए भी होगी। इस प्रकार, विश्वविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा प्रणाली को उच्च शिक्षा प्रणाली की उत्पादकता वर्ष 2015 तक वर्तमान 11 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, वर्ष 2020 तक 30 प्रतिशत और वर्ष 2040 तक 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। अन्य भारतीय जो उच्च शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं किए जाते हैं उनके पास निर्माण, बढ़ईगिरी, विद्युत प्रणाली, यांत्रिक प्रणालियों की मरम्मत, फैशन डिज़ायन, अर्द्धकानून, अर्द्धचिकित्सा, लेखाविधि, बिक्री और विपणन, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रखरखाव और सेवा, सॉफ्टवेयर गुणवत्ता विश्वास जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय कौशल होने चाहिए। कोई भी भारतीय युवा बिना विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा या बिना विश्वस्तरीय कौशल के नहीं होना चाहिए। यह एक महत्त्वपूर्ण कार्य है और सभी विश्वविद्यालय, शैक्षिक विशेषज्ञ, कॉलेज, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रमाणन एजेंसियां, बैंकिंग प्रणालियां और औद्योगिक उद्यम सही-सही संख्या के आकलन, राष्ट्र निर्माण कार्यों के प्ररूपण, बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं का आकलन और उन्हें उपलब्ध करवाने, अध्यापकों की गुणवत्ता सुधारने, अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात सुनिश्चित करने, दूर शिक्षा के जरिए वर्चुअल कक्षा के साथ कक्षा की पढ़ाई को जोड़ने और सबसे बढ़कर, विद्यार्थियों को रोजगार योग्य कौशल में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। प्रणालियां इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि कोई भी इच्छुक और सक्षम विद्यार्थी श्रेष्ठ शिक्षा हासिल करने से वंचित न रहे। शिक्षा प्रणाली आवश्यक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में सक्षम होनी

चाहिए। ये उदाहरण हैं जिनके द्वारा सरकार और शिक्षा प्रणाली संचालक हमारे युवाओं को अनुकूल माहौल प्रदान कर सकते हैं। तभी हमारे युवा राष्ट्र को समृद्ध बनाने में अपने ज्ञान कौशल का प्रयोग कर सकते हैं।

उद्यमशीलता का विकास

उद्यमशीलता की ओर उन्मुखता विद्यालय स्तर से शुरू होनी चाहिए। अध्यापकों को स्कूलों में राष्ट्रीय विकास में उद्यमशीलता की भूमिका के बारे में पढ़ाना चाहिए। कॉलेज शिक्षा के दौरान, विद्यार्थियों को व्यवसाय विकास अवसरों से परिचित करवाना चाहिए और उन्हें नए उद्यमों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के बाद नए उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें यह मानसिकता अपनानी चाहिए कि 'विचार ही सम्पत्ति है।' सरकार को अप्रत्यक्ष सुरक्षा रहित नवीन विचारों के लिए उद्यम पूंजी के प्रावधान हेतु अनुकूल माहौल तैयार करना चाहिए। विश्वविद्यालय, इंजीनियरी और प्रबंधन संस्थानों को प्रक्रिया सरल बनाने और परियोजना के आत्मनिर्भर और व्यावहारिक बनने तक उद्यमियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए बैंकों और वित्त एजेंसियों के साथ सहयोग करना चाहिए। सरकारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा के लिए बराबर का स्तर निर्मित करके नयी भारतीय प्रतिभाओं को ढूंढ़ना चाहिए और उनकी पहचान करनी चाहिए। बड़े और छोटे उद्योगों को युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उनका साझीदार बनना चाहिए।

गृहिणियों की भूमिका

परिवार को सही संस्कार देने के अलावा गृहिणियों की एक और महत्त्वपूर्ण भूमिका है। वे सामाजिक उत्थान में बराबर का योगदान दे सकती हैं। मैंने कोयम्बतूर में आरम्भ की गई 'सिरुथुलि' नामक एक परियोजना देखी है। व्यापक पैमाने पर वर्षा जल संचयन और जलाशयों की सक्रियता, वनीकरण, मलजल और अपशिष्ट जल के शोधन और ठोस कचरे के प्रबंधन से संबंधित इस परियोजना में समाज के सभी वर्गों के बहुत से लोग शामिल हैं। एक गृहिणी इस परियोजना का नेतृत्व कर रही है। देश की बहुत-सी पंचायतों की सदस्य महिलाएं हैं और वे अनेक ग्रामीण विकास कार्यों को अपना नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। छह लाख गांवों में ऐसे कार्यों से कितना अंतर आ सकता है, जरा उसकी कल्पना कीजिए।

पर्यावरण

नागरिकों की देशव्यापी सक्रिय भागीदारी के जरिए पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है। लोग एक समूह के तौर पर कोली बेयन नदी की तरह पर्यावरण स्वच्छ बनाने में

भागीदार बन सकते हैं। धार्मिक नेता स्वच्छ पर्यावरण आंदोलन में श्रद्धालुओं को शामिल करने की दिशा में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, इससे निश्छल विचारों का विकास होगा। स्थानीय रिहायशी-क्षेत्रों में साफ-सफाई का प्रदर्शन करने और उसके विषय में लोगों को शिक्षित करने के लिए स्थानीय समूह तैयार किए जा सकते हैं। वेलफेयर एसोसिएशन, एन सी सी कैडेट, स्काऊट्स और एन.एस.एस. स्वयंसेवक सक्रिय होकर ऐसे समूह बना सकते हैं। उद्योगपतियों को अपने सभी संस्थानों में पर्यावरणीय मानकों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए और इमारतों को विकलांग लोगों के अनुकूल बनाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को अपने दफ़्तर और पर्यावरण को अपने घर की तरह साफ-सुथरा रखना चाहिए। अभिभावकों और अध्यापकों को पर्यावरण संबंधी ज़रूरतों के बारे में युवा नागरिकों को शिक्षित करना चाहिए। नागरिक प्रत्येक वर्ष एक मिशन के रूप में अपने आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण कर सकते हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं। हमारी सार्वजनिक बुनियादी सुविधाएं, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बंदरगाह और अस्पताल विश्व पर्यावरण में राष्ट्र की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इन सभी सार्वजनिक सुविधाओं में स्वच्छता को बढ़ावा देना नागरिकों के साथ-साथ सभी वर्गों की जिम्मेदारी है।

विकसित भारत के लिए राजनैतिक प्रणाली में युवाओं की भागीदारी

युवाओं को बड़ी संख्या में राजनीति को अपना कैरियर बनाना चाहिए। स्कूलों में उच्चतर कक्षाओं और कॉलेज स्तर तक सभी विद्यार्थियों को विकास की राजनीति पर विशेष बल देते हुए राजनीतिशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। सक्रिय उम्मीदवारों के निष्पादन को ध्यान में रख उनका चयन करने के लिए नागरिकों को ईमानदारी से मतदान करना चाहिए। कानूनविदों, विशेषज्ञों और पेशेवरों को राजनीतिक प्रक्रिया, संविधान, कार्यप्रणाली, अधिकारों व कर्त्तव्यों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करना चाहिए।

इसी प्रकार, हर नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा, एक केंद्रित मिशन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की स्थिति में सुधार, कृषि सुधारों को गति प्रदान करने जैसे ऐसे और कई महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। इसी प्रकार न्यायपालिका भी जिला अदालतों, उच्च न्यायालयों में अगले तीन वर्ष में सभी लम्बित मामलों को समयबद्ध सीमा में निपटाने का एक अभियान चला सकती है। न्यायपालिका और अदालतों द्वारा आम आदमी को शीघ्र और सही न्याय दिलवाना चाहिए। लोग चाहते हैं कि हमारा पुलिस बल पारदर्शी और कार्योन्मुख होना चाहिए। इसके लिए पुलिस थानों को इलैक्ट्रोनिक संयोजन प्रदान करना भी बहुत जरूरी है और साथ ही उन्हें बेहतर जीवन स्तर जैसे उचित मकान, साफ-सफाई की सुविधाएं, चिकित्सा सेवाएं और बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी। इससे वे अपना कार्य एकाग्रता से

कर पाएंगे और उनके निष्पादन में सुधार आएगा। हमारी कुल जनसंख्या में से 50 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है। हमें उनके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें पंचायत प्रणाली जैसी निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारी पंचायतें वास्तव में ग्रामीणों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके क्षेत्र के ग्रामीण विकास के लिए आवंटित राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए न होकर सही उद्देश्य के लिए ही हो। प्यारे दोस्तो, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भागीदारी से लोग राष्ट्रीय विकास अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। अब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करूंगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा

हमारी सशस्त्र सेनाएं और अर्द्धसैनिक बल जल, थल और नभ में हमारी सीमाओं की चौकसी करते हैं, किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सदैव सजग रहते हैं और राष्ट्रीय विकास की निरन्तर प्रगति में मदद करते हैं। 17000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर की अपनी यात्रा के दौरान मैंने स्वयं यह अनुभव किया कि शून्य से 35 डिग्री कम तापमान और तेज हवाएं भी हमारे जांबाज सैनिकों को नहीं डिगा सकतीं। जब मैं पनडुब्बी में था तो मैंने युवा नौसैनिकों और नौसेना अधिकारियों को हिन्द महासागर में शान्त समुद्र की निरन्तर निगरानी के अपने मिशन पर सतर्कता और कुशलतापूर्वक कार्य करते देखा। मैं भारतीय वायु सेना की 20 स्क्वाड्रन के साथ था तो मुझे अनुभव हुआ कि हमारे लड़ाकू पायलट रडार मिसाइल और ई.डब्ल्यू. प्रणाली द्वारा किसी भी बहुलक्षीय चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम अपनी सशस्त्र सेनाओं के बहादुर सैनिकों की कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा, वचनबद्धता और शूरवीरता की कद्र करते हैं। हमारा पुलिस बल और गुप्तचर एजेंसियां एक दूसरे की पूरक हैं। ये हमारे नागरिकों को असामाजिक तत्त्वों, अपराधियों और अतिवादियों से बचाती हैं और सुरक्षित रखती हैं। इन बलों के बहुत से कार्मिकों ने देश की, उसके झण्डे की और लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहूति दी है। हम उन सबको सलाम करते हैं। हमारे कॉलेजों को श्रेष्ठ उद्यमी, अनुसंधानकर्त्ता ही नहीं बल्कि देश के लिए श्रेष्ठ सैनिक भी तैयार करने होंगे। अभिभावकों को अपने बच्चों को राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

बच्चे हमारी सम्पत्ति हैं

अबोध बच्चों के प्रति हाल ही की कुछ घटनाओं ने संपूर्ण राष्ट्र को झकझोर दिया और ये घटनाएं हम सबके दिलों पर गहरे घाव छोड़ गई हैं। बच्चे हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। बच्चों के प्रति निर्ममता हमारी सामाजिक संरचना के खिलाफ़ है। इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं

किया जाएगा। सम्मिलित कार्रवाई के रूप में सजग पड़ोसी, तीव्र कार्योन्मुख पुलिस तंत्र, सतर्क मीडिया और न्याय प्रणाली द्वारा अपराधी को तत्काल सजा देना समय की मांग है। इसके अलावा ऐसे अपराधों को रोकने के लिए हमें आधुनिक मनोवैज्ञानिक जांच की सहायता से समाज के ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों की पहचान करना होगी। बच्चों के प्रति क्रूरता समाप्त करना प्रत्येक भारतीय का मिशन होना चाहिए क्योंकि वे हमारा भविष्य हैं।

निष्कर्ष

वर्ष 2020 तक विकसित भारत, एक अरब भारतीयों का एक मिशन है। प्रत्येक व्यक्ति को इसमें भूमिका निभानी होगी। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रव्यापी सहभागिता द्वारा सरकारी सहयोग से इस राष्ट्रीय अभियान में 'अपनी क्षमता अनुसार जो भी योगदान दे सके' तो यह मिशन साकार हो सकेगा। देश-विदेश में अपने देशवासियों और खासकर युवाओं से हुई बातचीत के दौरान प्रत्येक में मुझे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिला। उनमें भारत को विकसित बनाने के लिए, अपना संपूर्ण योगदान देने की उत्सुकता दिखाई दी। प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक समूह का योगदान देने का विचार निश्चित ही संपूर्ण राष्ट्र को समृद्ध बनाने का एक प्रमुख तत्त्व बनेगा और इससे विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी।

जब राष्ट्र अपने मिशन की ओर अग्रसर होगा तो इसके रास्ते में अनेक चुनौतियां भी आएंगी। इन चुनौतियों का मुकाबला करने की हिम्मत समाज के सभी तबकों की एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विशेषता होगी। मैं एक घटना का ज़िक्र करना चाहूंगा। 8 जून 2006 को मैं सुखोई-30-एमकेआई में उड़ान भर रहा था। विमान को विंग कमाण्डर अजय राठौर चला रहे थे। वह 40 मिनट की उड़ान थी। मैंने उड़ान की संपूर्ण कार्रवाई में भाग लिया। जब मैं विमान से नीचे उतरा तो अनेक युवा और मीडियाकर्मी मेरा इन्तजार कर रहे थे। एक युवक ने पूछा—श्रीमान राष्ट्रपति, कृपया बताएं कि क्या 74 वर्ष की आयु में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान में उड़ान के दौरान किसी भी वक्त आपको डर लगा? मैंने युवक को उत्तर दिया—40 मिनट की उड़ान के दौरान सारा वक्त मैं उसके उपकरणों और नियंत्रण में व्यस्त रहा और 'जी' (गुरुत्वाकर्षण) का अनुभव करता रहा। विमान के कप्तान ने मुझे सलाह दी थी कि मैं लक्ष्यों को देखने के साथ-साथ सिंथेटिक अपरचर रडार का उपयोग करते हुए धरती को देखता रहूं। इसके अलावा, मैं देश में ही निर्मित उपकरणों के निष्पादन पर भी ध्यान दे रहा था। मैं लगातार उड़ान की कार्यप्रणाली में व्यस्त रहा। इस दौरान मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं किसी भी प्रकार से भयभीत होता। प्यारे युवा दोस्तो, अब मैं आप सबको, जो यहां मेरे और राष्ट्र के सम्मुख एकत्रित हुए हैं, हिम्मत का एक संदेश दूंगा।

देने की हिम्मत

कुछ अलग सोचने की हिम्मत,
आविष्कार की हिम्मत,
असंभव को खोजने की हिम्मत,
अनखोजे रास्ते पर चलने की हिम्मत,
ज्ञान बांटने की हिम्मत
दुख दूर करने की हिम्मत
अप्राप्त को पाने की हिम्मत
कठिनाइयों का मुकाबला करने
और कामयाब होने की हिम्मत,
ये सभी, युवाओं की अद्‌भुत विशेषताएं हैं।

राष्ट्र के एक युवा के रूप में, मैं अपने सभी मिशनों में सफलता प्राप्त करने के लिए निरन्तर हिम्मत के साथ कार्य करूंगा।

मेरे प्यारे देशवासियो! एक बार फिर मैं आप सबको उद्देश्यपूर्ण और खुशहाल गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं।

ईश्वर की आप पर कृपा रहे।

जय हिन्द!